छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करो!
क्रांतिकारी जनताना सरकार ही
लुटेरी व्यवस्था का एक मात्र विकल्प है!
भ्रष्टाचारी, जन विरोधी, देशद्रोही और फासीवादी
कांग्रेस और भाजपा को मार भगाओ!

प्यारे भाइयो और बहनो!

जल्द ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सैकड़ों करोड़ रूपयों के भारी खर्चे से होने वाले इस 'उत्सव' का भार लुटेरे शासक वर्गों द्वारा छत्तीसगढ़ जनता पर फिर एक बार थोपा जा रहा है। इस मौके पर लुटेरे शासक वर्गों की प्रमुख संसदीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा सत्ता के लिए कड़ी टक्कर लेते हुए, फिर एक बार जनता को छलने के लिए कई पापड़ बेल रहे हैं। साम्राज्यावादियों द्वारा निर्देशित नीतियों को लागू करने में तथा सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों की सेवा करने में आगे रहने वाली ये दोनों मुख्य पार्टियां एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते हुए अपने दिवालिएपन का खुला प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 10 सालों से सत्तारूढ़ भाजपा ने महीनों पहले से 'विकास यात्रा' के नाम पर अपनी सरकार द्वारा हासिल 'विकास' के बारे में जोर शोर से प्रचार शुरू किया ताकि वह लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो सके। वहीं दूसरी ओर, लगातार दो बार हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस इस प्रयास में है कि किसी भी तरह इस बार सत्ता हथिया ली जाए। 'परिवर्तन यात्रा' के नाम से शुरू किए गए उसके चुनावी अभियान पर झीरमघाटी हमले से अस्थाई रोक लगी थी, जिसे दुबारा 'बलिदानी माटी कलश यात्रा' के नाम से शुरू किया गया ताकि जनता की 'सहानुभूति' को वोटों में तब्दील किया जा सके। वहीं दूसरी ओर संशोधनवादी पार्टियां भाकपा, माकपा; खुद को दलित–बहुजनों का चैम्पियन होने का दावा करने वाली बसपा; और एनसीपी, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, गोण्डवाना गणतंत्र पार्टी आदि अन्य चुनावी पार्टियां गठजोड़ बनाकर तीसरे मोर्चे के नाम से चुनावी दंगल में उतर रही हैं। पी.ए. संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी इस गठबंधन में शामिल न होकर अलग से लड़ रही

है। ये सभी चुनावी पार्टियां वोट पाने के लिए जनता का 'विकास' ही अपना लक्ष्य बताते हुए दमघोंटू प्रचार युद्ध चला रही हैं।

लेनिन ने 'राज्य और क्रांति' में यूं कहा था – ''केवल संसदीय–संवैधानिक राजतंत्रों में ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक जनवादी लोकतंत्रों में भी बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था का सच्चा सार कुछ वर्षों में एक बार यह फैसला करना ही है कि शासक वर्ग का कौन सदस्य संसद में जनता का दमन और उत्पीड़न करेगा।'' यह आज भी और हमारे देश में भी अक्षरशः सच है। यही वजह है कि शोषित जनता यह कतई विश्वास नहीं करती है कि इन चुनावों से उसकी जिन्दगी बदलेगी या इस व्यवस्था में मूलभूत बदलाव आयेगा। इसीलिए देश में कहीं भी और किसी भी चुनाव में उल्लेखनीय संख्या में लोग मतदान से दूर ही रह रहे हैं। मतदान करने वालों में भी ज्यादातर लोग इस उम्मीद से तो वोट नहीं डाल रहे हैं कि चुनावों से उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। बल्कि वे सिर्फ स्थानीय जरूरतों के लिए या जाति, धर्म, पैसा, गुण्डागर्दी आदि दबावों और प्रलोभनों से ही मतदान कर रहे हैं। या फिर सत्तारूढ़ पार्टी पर विरोध के चलते वोट दे रहे हैं। सच तो यह है कि विगत 65 सालों के 'स्वतंत्र' शासन में अनेकों बार चुनाव हुए, कई सरकारें बदलीं परंतु आज भी रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जनता की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाईं। आज भी 95 प्रतिशत उत्पीड़ित जनता भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, बीमारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से जूझ रही है। देश में 77 प्रतिशत जनता रोज 20 रूपये से भी कम आय पर बदहाली में गुजारा करने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ बड़े पूंजीपति और भूस्वामी बेहिसाब समृद्धि पा रहे हैं। अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, जिन्दल आदि महज सौ कार्पोरेट घरानों की कुल सम्पत्ति देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक चौथाई के बराबर है। इस व्यवस्था में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई अकथनीय स्तर तक बढ़ी है। भ्रष्टाचार, घोटालों में बेहिसाब वृद्धि हुई है। इस वजह से देश भर में सामाजिक अशांति बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रति जनता में कोई उत्साह नहीं है।

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, खासकर अविभाजित बस्तर में हमारी पार्टी के नेतृत्व में पिछले तीन दशकों से जारी जनयुद्ध के मद्देनजर शासक हर बार की तरह इस बार भी चुनावों को 'जनता पर युद्ध' के रूप में ही चलाने जा रहे हैं। क्रांतिकारी आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से पिछले चार सालों से जारी आपरेशन ग्रीनहंट के तहत शोषक शासक वर्ग इस चुनाव की आड़ में अपने हमलों में तेजी लायेंगे। इस दौरान गांवों पर आक्रमण, तलाशी अभियान, गिरफ्तारियां, फर्जी मुठभेड़ें लगातार चलाएंगे। हमारी पार्टी के नेतृत्व

में चलने वाले 'चुनाव बहिष्कार' अभियान को विफल करने के लिए और भी अर्द्धसैनिक बटालियनों, अतिरिक्त पुलिस बलों और कमांडो बलों को तैनात करने की तैयारियां कर रहे हैं। खासकर 25 मई को हुए ऐतिहासिक झीरमघाटी हमले में बस्तर जनता का जानी दुश्मन महेन्द्र कर्मा के साथ–साथ वी.सी. शुक्ल, नंदकुमार पटेल जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं के एक साथ मारे जाने से बौखलाए शासक वर्गों ने और ज्यादा क्रूर व फासीवादी तरीकों में हमलों की योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 जून को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में एकमत से निर्णय लिया गया कि माओवादी आंदोलन को कड़ाई से कुचल दिया जाए। गौरतलब है कि चुनावों को 'निष्पक्ष' और 'स्वतंत्र' रूप से संचालित करने के नाम पर यहां यह दमनचक्र चलाया जा रहा है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं कि हर बार की तरह यह चुनाव भी, खासकर संघर्षरत इलाकों में बंदूक की नोंक पर ही संचालित होगा। इसलिए हमें शोषक शासक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे इन क्रूर हमलों का प्रतिरोध करते हुए चुनाव बहिष्कार के लिए राजनीतिक तौर पर तैयारियां करने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान चुनाव में आगे आ रही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की स्थिति का जायजा लें।

मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा अपने आपको कब का कट्टर व फासीवादी धर्मोन्मादी के रूप में साबित कर चुकी है। पिछले दस सालों से राज्य की जनता उसके फासीवादी शासन को झेल चुकी है। वह केन्द्र में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके और ज्यादा फासीवाद की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। और गुजरात नमूने को देशभर में लागू करने के लिए उतावली हो रही है। देश को हिन्दू राज्य में बदलने के दुष्टतापूर्ण सिद्धांत पर अमल करने में ज्यादा आक्रामकता दिखाने वाले मोदी की धाक पार्टी में बढ़ी है, जिससे यह खतरा बढ़ गया है कि राज्य में अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो हिन्दू धर्मोन्माद और ज्यादा बढ़ जाएगा। यह राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बल्कि आदिवासी जनता के अस्तित्व और अस्मिता के लिए भी खतरा है।

वहीं पिछले दस सालों से यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी ने देश को सभी क्षेत्रों में बर्बाद कर रखा है। यूपीए सरकार ने 2जी स्प्रेक्ट्रम, कामनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, कोयला घोटाला जैसे कई महाघोटालों में लाखों करोड़ रुपयों के जनधन को डकार लिया। देश की सार्वभौमिकता को गिरवी रखकर साम्राज्यवादियों के साथ कितने ही समझौते कर रखे हैं। वह विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश के लिए सारे दरवाजे खोलकर देश में दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू कर रही है। कांग्रेस ने करोड़ों खुदरा व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए खुदरा क्षेत्र को पूरी तरह

साम्राज्यवादी कम्पनियों के हवाले करने की नीतियां अपनाई हैं। वह देश की खनिज सम्पदाओं को कार्पोरेट संस्थाओं के हवाले कर देश को खोखला बना रही है। जनता को विस्थापित कर रही है। इस तरह केन्द्र के यूपीए नमूने को कांग्रेस पार्टी दस सालों के बाद सत्ता हासिलकर राज्य में अमल करने के लिए उत्सुक हो रही है।

इसीलिए वे जनता को फिर एक बार धोखा देने सामने आ रही हैं।

सत्ताधारी भाजपा पिछले पांच सालों में, कुल मिलाकर दस सालों के अपने शासन काल में प्रदेश में कई गुना 'विकास' करने का खूब ढिंढोरा पीट रही है। अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक सम्पदाओं, जिन पर जनता का जायज हक बनता है, को बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों को कौड़ियों के भाव बेचते हुए वह विभिन्न झूठे सुधार कार्यक्रमों का बढ़ा–चढ़ाकर प्रचार कर रही है। मुख्य रूप से वह अपनी झूठी विकास योजनाओं को इसके आधार के रूप में दिखा रही है। वहीं उसने बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की लूटखसोट के लिए बनाई गई योजनाओं या उनको दी जा रही रियायतों के मामले में चुप्पी साध रखी है। गरीब जनता को सस्ते में चावल, दाल, मुफ्त में नमक देने की योजना को अमल करने का श्रेय लेते हुए रमनसिंह खुद को 'चऊंर वाले बाबा' के रूप में महिमामंडित करवा रहे हैं। कार्पोरेट शोषण को आसान करने के लिए जारी सड़क निर्माण, बिजली संयंत्र जैसी परियोजनाओं को ही 'जनता के विकास' के रूप में दिखाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। रमनसिंह सरकार द्वारा नवम्बर 2012 में रायपुर में 'क्रेडिबल छत्तीसगढ़' के नारे के साथ आयोजित 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' छत्तीसगढ़ की सम्पदाओं को औने–पौने दामों में बेचकर करोड़ों रूपयों की कमिशनों से मंत्रियों और अधिकारियों की जेबें भरने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है।

केन्द्र सरकार मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को साल में सौ दिन मजदूरी का काम दे रही है, जबकि रमन सरकार 50 दिन का अतिरिक्त काम देने और उसके लिए अलग से बजट मंजूर करने का ढिंढोरा पीट रही है। सच्चाई यह है कि प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत 43 प्रतिशत काम भी नहीं हुए हैं। जितना हुआ है उसमें भी गांव के सरपंच, सचिव से लेकर मंत्रियों, कलेक्टरों तक बेहिसाब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बात को हम किसी भी गांव में जाकर जान सकते हैं। काम न होने पर भी कागजों पर हाजरी दिखाकर, पासबुक में झूठे हस्ताक्षर कर मजदूरों को देय करोड़ों रूपयों के जनधन के गबन की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून के नाम पर गरीब परिवारों को एक/दो रुपये में 35 किलो चावल, आदिवासी इलाकों में 5 रुपए किलो की दर पर चना और अन्य क्षेत्रों में 10 रुपये किलो की दर पर दो किलो दाल देने की योजना का रमनसिंह सरकार खूब प्रचार कर रही है। इसे अमल करने में वह छत्तीसगढ़ सरकार ही सबसे आगे होने का दावा कर रही है। दरअसल, यहां गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने इस सम्बन्ध में यह फैसला सुनाया था कि गोदामों में सड़ रहे खाद्यान्न को जनता को मुफ्त में बांटा जाए। परन्तु इसमें भ्रष्टाचार किस स्तर पर हो रहा है इसे जानने के लिए किसी भी अखबार के पन्ने पटलना ही काफी होगा। राशन दुकानों की बजाए चावल के सीधा चोर व्यापारियों के गोदामों में पहुंचने की कितनी ही खबरें हैं। और मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों में तो एक महीना चावल मिलता है तो फिर तीन–चार महीनों के बाद ही उम्मीद की जा सकती है। चावल कब आता है और कब खत्म हो जाता है पता तक नहीं चलता। रमनसिंह के कथन के मुताबिक अगर हर महीना यह योजना सही तरीके से अमल होती भी है तो दिनभर मेहनत करने वाले श्रमिक परिवारों को ये 35 किलो चावल एक सप्ताह के लिए भी काफी नहीं है। साल में मात्र कुछ दिनों तक मिलने वाली मजदूरी से जिन्दगी को घसीट रहे गरीबों को बाकी तीन सप्ताह के भोजन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे आसानी से समझा जा सकता है। बाजार में जहां चावल की कीमत 20–25 रुपया प्रति किलो हो, ऐसे में गरीबों के सामने भूखे पेट रहने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जल्दबाजी दिखाते हुए 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून' को लाया है। मुठ्ठी भर कार्पोरेट वर्गों को 5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा कर रियायतों की खुशी से घोषणा करने वाली कांग्रेस पार्टी देश की 70 प्रतिशत जनता की 'खाद्य सुरक्षा' के लिए केवल 1.3 लाख रुपयों की घोषणा करके गरीबों की भूख पूरी तरह मिटाने की ऊंची बातें कर रही है। दुनिया के 25 प्रतिशत भूखे लोग हमारे ही देश में हैं और इस कानून के द्वारा सरकार हर आदमी को महीने में सिर्फ 5 किलो चावल देकर पेट भर डालने का विश्वास दिला रही है।

वास्तव में सरकारें इन योजनाओं को जनता पर प्रेम से नहीं ला रही हैं। साम्राज्यवाद–निर्देशित आर्थिक नीतियों को सिर आंखों पर बिठाने के चलते जनता के दिलों में सुलग रहे गुस्से को ठंडा करने के लिए ही इन्हें लाई जा रही हैं। इस तरह की योजनाएं गरीब जनता के लिए कुछ हद तक सहारा हो सकती हैं लेकिन, जनता की जिन्दगी में मूलभूत बदलाव तो कतई नहीं ला सकतीं। अपने अनुभवों से जनता यह जान चुकी है कि कोई भी लुटेरी राजनीतिक पार्टी

उसकी जिन्दगी को नहीं बदल सकती। और आज उसने संघर्ष की राह पकड़ रखी है। उन संघर्षों से जनता को गुमराह करने के लिए ही यह नौटंकी! उतना ही नहीं, सरकार अपनी पार्टी के ऊपर से लेकर ग्राम स्तर के नेताओं तक को इन योजनाओं के नाम से आने वाले धन का गबन करने की छूट देकर एक तबके को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रही है। वास्तव में रमन सरकार ने इन दस सालों में जनता के सही विकास के लिए कुछ भी नहीं किया।

कृषि क्षेत्र के प्रति, जिस पर अत्यधिक आबादी निर्भर है, सरकार घोर लापरवाही बरत रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों को पूरा करते हुए वह किसानों की जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं के साथ किए समझौतों के मुताबिक कृषि क्षेत्र को धीरे–धीरे कार्पोरेट घरानों के हवाले करना ही उसका लक्ष्य है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आज भी बेहद कम जमीनों को ही सिंचाई का पानी मिल रहा है जबकि अत्यधिक जमीनें बारिश के भरोसे हैं। वर्ष 2000 से 2011 के बीच प्रदेश में 14,340 किसानों ने खुदकुशी कर ली। 'धान का कटोरा' कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान का जीना ही मुश्किल हो गया।

जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों का ताल्लुक है, उनकी बदहाली जगजाहिर है। इन क्षेत्रों को कार्पोरेट कम्पनियों के हवाले कर शोषित जनता को धीरे–धीरे इन सुविधाओं से दूर ही धकेला जा रहा है। जनता की जरूरतों के अनुसार सरकारी स्कूलें नहीं हैं। राज्य भर में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती न करते हुए शिक्षाकर्मियों के जरिए ही काम निपटाया जा रहा है। और आदिवासी इलाकों में हालात और भी बदतर हैं। इन इलाकों में शालाओं की स्थिति पहले से लचर है और अब तो सरकार अंदरूनी गांवों में मौजूद प्राथमिक, माध्यमिक और आश्रम शालाओं को विकासखण्ड मुख्यालय में और पक्की सड़कों से जुड़े गांवों में बदल रही है। दूसरी ओर एजुकेशन हब, पोटा केबिन, गुजर–बसर कालेज के नाम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कई स्कूलों में सरकारी सशस्त्र बलों ने डेरा जमाया है जोकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी खुली अवमानना है। कुल मिलाकर अंदरूनी गांवों में आदिवासी और गैर–आदिवासी जनता को आज भी शिक्षा सुविधाओं से वंचित ही रहना पड़ रहा है।

गिने–चुने ही रह गए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती न करने के कारण घोर बदहाली छाई हुई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से 'स्मार्ट कार्ड' के जरिए गरीबों

का मुफ्त में इलाज करवाने का डींग मारने वाली सरकार दरअसल कार्पोरेट अस्पतालों के मालिकों से सांठगांठ कर भारी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कर रही है। फलस्वरूप प्रदेश में, खासकर आदिवासी इलाकों में हर साल बीमारियों के चलते लोग बेमौत मर रहे हैं। और पिछले साल सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के गर्भाशय हटाने के मामलों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया।

जहां एक ओर सरकार यह ढिंढ़ोरा पीट रही है कि प्रदेश में बिजली का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लोवोल्टेज की समस्या से किसानों के पानी के इंजनों के जल जाने के कई वाकए सामने आ रहे हैं। कार्पोरेट वर्गों को बेरोकटोक और कई रियायतों के साथ बिजली की आपूर्ति करने वाली रमन सरकार जनता को अंधकार में धकेल रही है। दूसरी ओर उसने राज्य विद्युत मण्डल का निजीकरण करने की कोशिशें शुरू कर प्रदेश की जनता, खासकर हजारों कर्मचारियों और मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है।

जनता को, खासकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में रमन सरकार बुरी तरह विफल हो गई। जन संघर्षों का दमन करने के लिए लगातार बढ़ाए जा रहे पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों में भर्ती को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में भर्तियां बंद हैं। विश्व बैंक द्वारा निर्देशित नीतियों को सिर माथे पर लिए हुई रमन सरकार पिछले पांच सालों में किसी भी क्षेत्र में रिक्त पदों की भर्ती नहीं की। और मजदूर वर्ग की जहां तक बात है, वह भी कई समस्याओं से परेशान है। राज्य में प्रमुखता से मौजूद असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को आज भी 10 से 12 घण्टे तक काम करना पड़ता है जोकि शर्मनाक है। न्यूनतम वेतन कानून की हर ओर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बोनस, बीमा, छुट्टी आदि न्यूनतम श्रम कानूनों का भी खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो रहा है। काम की जगहों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों के प्रति मालिक और प्रबंधन आपराधिक लापरवाही बरत रहे हैं जिससे बाल्को समेत कई छोटे–बड़े कारखानों में हुए हादसों में दर्जनों की संख्या में मजदूर मारे गए। लेकिन नेता–मंत्रियों और अफसरों को घूस खिलाकर पूंजीपति बिना किसी केस में फंसे साफ बच जाते हैं।

गरीब जनता की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति तक नहीं करने वाले शासक, कार्पोरेट आकाओं के स्वागत में तो लाल कालीन बिछा रहे हैं। रमनसिंह जो 'विकास' का राग आलाप रहे हैं उसका एक मुख्य हिस्सा है उसकी औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति (2009–14) में सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि उसे

बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के संगठनों के साथ चर्चा करके बनाया गया था। सरकार का यह भी कहना है कि बड़े पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों को आकर्षित करने और सौ फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश को आमंत्रित करने के लिए यह नीति बनाई गई है। इसमें पूंजी की सेवा में जमीनें अधिग्रहित करके देने, औद्योगिक परिवहन के लिए रेलवे, सड़कें और हवाई अड्डों को विकसित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों, सब–हाइवे और रिंग रोड का निर्माण करने, उद्योगों को मुफ्त में बिजली, पानी और कई अन्य रियायतें देने आदि ढेरों वादे रमन सरकार ने किए। अनिवासी भारतीयों और सौ फीसदी एफडीआई के साथ आने वाले पूंजीपतियों को अन्य लोगों से 5 प्रतिशत अधिक रियायतें देने की घोषणा करके वह किन वर्गों का हितपोषण कर रहा है, इसे आसानी से समझा जा सकता है।

बैलाडीला से निकलने वाले लौह अयस्क को, जोकि एशिया में सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, सरकारें बेहद सस्ते में जापान को बेच रही हैं। वहीं राज्य में कई स्पंज आयरन कारखाने कच्चामाल के अभाव में और महंगी दरों के चलते बंद पड़ते जा रहे हैं। छोटे और मध्यम श्रेणी के पूंजीपति कई सालों से रमन सरकार से यह गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बैलाडीला से कच्चामाल उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन इससे रमन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। दूसरी ओर वह पुष्पा स्टील्स जैसे अपने प्रिय पूंजीपतियों को मनमाने माइनिंग के लाइसेंस दिए। इस तरह वह माइनिंग माफिया, बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हितों की रक्षा करते हुए देशी पूंजीपतियों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। उसकी औद्योगिक नीति भारी कार्पोरेट कम्पनियों को बेतहाशा मुनाफा पहुंचाने वाली ही है। उन्हें छत्तीसगढ़ की सम्पदाओं का दोहन करने के तमाम अवसर प्रदान करने वाली इस नीति से बेरोजगारों को रोजगार मिलने का दावा सरासर झूठ है। बड़े और विदेशी पूंजीपतियों के साथ किए सैकड़ों एमओयू के फलस्वरूप जो कम्पनियां यहां आ रही हैं या आएंगी वो सब भारी तकनीक पर आधारित ही होंगी। उच्च तकनीकी योग्यता से लैस चंद लोगों को छोड़कर मामूली रूप से पढ़े–लिखे बेरोजगारों को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे छत्तीसगढ़ में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन की समस्या के हल होने का दावा तो दूर की कौड़ी है।

आदिवासी इलाकों में अमल के लिए बनी संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा (ग्रामसभा) आदि कानूनों और नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। बंदूक की नोंक पर ग्रामसभाओं का आयोजन कर जनता को जबरन जमीन अधिग्रहण के लिए राजी किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र के नगरनार, लोहण्डीगुड़ा,

भांसी–धुरली, रावघाट, आमदायमेट्टा, पल्लामाड़, कलवर, कच्चे में हो या फिर रायगढ़ जिले के तमनार (जिंदल), धरंजयगढ़ आदि इलाकों में हो, हमें साफ समझ में आता है कि सरकार किस तरह अपने ही बनाए कानूनों का उल्लंघन कर जनता को विस्थापित कर रही है। और हाल में संसद द्वारा पारित जमीन अधिग्रहण कानून भी जनता से बड़े पैमाने पर जमीनें छीनकर कार्पोरेट वर्गों के हवाले करने की नीयत से ही बनाया गया था। दूसरी ओर जल–जंगल–जमीन की रक्षा के लिए और उस पर अपना अधिकार कायम करने के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेज दिया जा रहा है। सैकड़ों लोगों पर माओवादी का ठप्पा लगाकर उनके खिलाफ राजद्रोह के मामले भी लगाए जा रहे हैं।

आदिवासियों के साथ हुए 'ऐतिहासिक अन्याय' को सुधारने के नाम पर संसद द्वारा पारित 'वन अधिकार कानून, 2006' आज तक कहीं भी लागू नहीं हुआ। दरअसल यह आदिवासियों को धोखा देने के लिए ही बनाया गया कानून था, न कि उनका भला करने वाला। इस कानून को लेकर चाहे कितनी ही लम्बी–चौड़ी बातें कही जाएं, देश के करोड़ों आदिवासियों और वन निवासियों को आज तक अपनी जमीनों पर अधिकार मिला ही नहीं। और तो और उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीनों को कार्पोरेट कम्पनियों और सरकारी आक्रमण से बचाने के लिए जीवन–मरण का संघर्ष करना पड़ रहा है।

आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भाजपा का असंतुष्ट गुट और कांग्रेस समेत कुछ अन्य पार्टियों के नेता सामने ला रहे हैं। पिछले दस सालों में आदिवासियों का कत्लेआम करने वाले, आदिवासियों के अधिकारों का खुला हनन करने वाले और आदिवासियों की जमीनें कार्पोरेट घरानों के हवाले करने वाले आज आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार वो यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आदिवासियों को कुछ हासिल हो पाएगा। दरअसल चाहे आदिवासी हो, या दलित हो या फिर महिला या अल्पसंख्यक कोई भी मुख्यमंत्री बने, या प्रधानमंत्री बने या फिर राष्ट्रपति ही क्यों न बने, इससे आदिवासियों और अन्य उत्पीड़ित तबकों को कुछ खास मिलने वाला नहीं है। मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी और शासक वर्गों द्वारा लागू मौजूदा शोषणकारी नीतियों का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक शोषित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। वर्तमान इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलेंगे। यह जगजाहिर है कि आदिवासी नेता के रूप में आगे आकर महेन्द्र कर्मा ने आदिवासी जनता के लिए क्या किया था।

रमन के दस साल के शासन में कर्मचारियों के हितों को कितनी चोट पहुंची इसे समझने के लिए हाल में लगातार हुई हड़तालों का सिलसिला एक उदाहरण भर है। जोगी के शासनकाल के आखिर में, 2003 में जब शिक्षाकर्मियों ने हड़ताल की थी तो भाजपा ने यह आश्वासन दिया था कि उसके सत्ता में आते ही उनकी समस्याओं का निरारकरण किया जाएगा। लेकिन अपने वादे से मुकरते हुए उसने मात्र सौ रुपए की वेतन वृद्धि करके पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद भी शिक्षाकर्मियों ने कई बार हड़तालें कीं फिर भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। हाल ही में शिक्षाकर्मियों ने 38 दिनों तक लगातार हड़ताल की तो उसे दबाने के लिए रमन सरकार ने हर किस्म के हथकण्डे अपनाए थे। निराशा के चलते दसियों की संख्या में शिक्षाकर्मियों ने आत्महत्या की। इस पृष्ठभूमि में आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके वेतनों में नाम मात्र की बढ़ोत्तरी भले ही की हो लेकिन उनकी 'समान काम के लिए समान वेतन' की प्रधान मांग आज भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा शिक्षकों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, पंचायत सचिवों, वन विभाग के कर्मचारियों, पटवारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम..... इस तरह हर विभाग के कर्मचारियों ने रमन सरकार द्वारा लागू कर्मचारी विरोधी नीतियों से तंग आकर कई बार हड़तालें कीं। हालांकि सरकार ने हर बार और हर हड़ताल का दमन करने की ही कोशिश की। पिछले दस सालों के शासन में हड़तालों के दौरान शिक्षाकर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया जुल्म के कई वाकए हुए थे।

रमन सरकार द्वारा घोषित महिला नीति कितनी 'बढ़िया' है इसे समझने के लिए मीना खल्खो और सोनी सोड़ी के प्रकरण काफी होंगे। 'महिला सशक्तिकरण' जैसे शब्दों के मायाजाल को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं के हित में उसने कुछ खास किया ही नहीं। यह कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि 'महिला उत्पीड़न' के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सरकार के आदेश पर सोनी सोड़ी के साथ अमानवीय अत्याचार किया तो उसके लिए जिम्मेदार एस.पी. अंकित गर्ग को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के हाथों 'वीरता पुरस्कार' दिलवाया गया। नाबालिग लड़की मीना खल्खो पर सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले पुलिस वालों को रमन सरकार ने आज तक छूआ भी नहीं। कांकेर जिले के पथारी गांव की दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले जंगल वारफेर कालेज के कर्मचारियों को रस्मी तौर पर गिरफ्तार कर बाद में छोड़ दिया गया। और झलियामारी काण्ड तो लड़कियों के प्रति, खासकर आदिवासी छात्राओं के प्रति रमन सरकार द्वारा बरती जा रही आपराधिक लापरवाही की एक मिसाल भर है। इधर क्रांतिकारी आंदोलन वाले

इलाकों में तैनात अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, कोया कमाण्डो/एसपीओ (फिलहाल सहायक आरक्षकों) द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों और जुल्मों का हिसाब ही नहीं है। इनसे सम्बन्धित खबरों को अखबारों में बहुत कम ही जगह मिल पाती है।

रमन सरकार द्वारा जारी दुष्प्रचार फासीवादी जर्मनी के प्रचार मंत्री गोबेल्स के सिद्धांत से ठीक मेल खाता है। एक झूठ को सौ बार दोहराने से वह 'सच' होकर रहेगा – इस सिद्धांत के मुख्य माध्यम के रूप में यहां का कार्पोरेट मीडिया काम कर रहा है। ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ से प्रकाशित 'दैनिक भास्कर', 'हरिभूमि' आदि अखबार रमनसिंह सरकार के मुखपत्र के तौर पर काम कर रहे हैं। लगभग तमाम बड़े अखबारों और टीवी चैनलों के मालिक वही कार्पोरेट चोर–लुटेरे हैं जो छत्तीसगढ़ में जारी संसाधनों की लूटखसोट में भागीदार हैं। दण्डकारण्य में जारी आपरेशन ग्रीनहंट के अंतर्गत शासक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' में अखबार और टीवी चैनल अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। वे रमनसिंह सरकार द्वारा अमल तमाम दमनकारी नीतियों पर पर्दा डालते हुए उसके जन विरोधी और विनाशकारी नव उदार नीतियों पर 'विकास' का रंग चढ़ा रहे हैं। इस दुष्प्रचार अभियान पर रमन सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अपने पक्ष में खड़े मीडिया मालिकों और प्रतिनिधियों को कई रियायतें देकर आर्थिक रूप से फायदे पहुंचा रही है और रिश्वत दे रही है। वहीं उसकी नीतियों की जरा भी आलोचना करने वाले पत्रकारों और अन्य मीडिया प्रतिनिधियों को वह कई प्रकार के दबावों और हमलों का शिकार बना रही है।

कार्पोरेट मीडिया रमनसिंह की 'स्वच्छ छवि' का चाहे जितना भी ढिंढ़ोरा पीट ले, सच यह है कि खुद वह और उनकी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार–घोटालों का कोई हिसाब नहीं रहा। कैग की रिपोर्ट से यह पता चला कि 'कोलगेट' के नाम से कुख्यात ताजा कोयला घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने को एक हजार करोड़ रुपए की सेंध लगी है। लेकिन इसे रमनसिंह ने रफा–दफा कर डाला। अपना लंगोटिया यार और भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन गड़करी के करीबी अजय संचेती को दसियों हजार करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाते हुए कोयला खण्डों का आवंटन करना, कई अन्य को नियमों के खिलाफ प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस जारी करना, तेंदुपत्ता ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत लेना आदि कई घोटाले एक के बाद एक सामने आए। हाल ही में कांग्रेसियों द्वारा जारी एक सीडी से यह पता चला कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक डिपाजिटों के घोटाले में मुख्य आरोपी उमेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री रमनसिंह समेत बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, रामविचार नेताम आदि मंत्रियों को रिश्वत

देने की बात कबूली थी। इस घोटाले में 25 हजार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की गाढ़ी कमाई 53 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके थे। इस तरह इन दस सालों में ऐसे कई घोटाले उजागर हुए और कई अन्य दब भी गए।

भाजपा सरकार ने पिछले दस सालों में जनता पर, खासकर आदिवासियों पर बेहद अमानवीय दमन का प्रयोग किया। 2005 में उसने केन्द्र की यूपीए सरकार के सहयोग से, प्रदेश के विपक्षी नेता महेन्द्र कर्मा के साथ सांठगांठ से 'सलवा जुडूम' के नाम से एक अत्यंत विनाशकारी दमन अभियान चलाया था। केन्द्रीय खुफिया संगठनों द्वारा सुनियोजित इस अभियान में धर्मोन्मादी आरएसएस से जुड़े कई हिंदू धार्मिक संगठनों ने भी सक्रिय भूमिका अदा की। इस हमले में 600 से ज्यादा गांवों को जला दिया गया। एक हजार से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। कई महिलाओं को क्रूर हिंसा और अत्याचारों का शिकार बनाया गया। घरों को लूटा गया। हजारों लोगों को जबरन 'राहत' शिविरों में घसीटा गया। हालांकि इस फासीवादी हमले का उत्पीड़ित जनता ने हमारी पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्व में वीरतापूर्वक प्रतिरोध कर उसे परास्त कर दिया। उसके बाद 2008 के अंत में प्रदेश में भाजपा फिर एक बार सत्तारूढ़ हुई। मई 2009 में यूपीए–2 का शासन शुरू हुआ। 2009 के मध्य से केन्द्र सरकार की अगुवाई में विभिन्न राज्य सरकारों ने मिलकर हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन पर अभूतपूर्व स्तर पर देशव्यापी भारी हमला शुरू किया। आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से जारी यह हमला अब कथित रूप से दूसरे चरण में पहुंच चुका है। शासक वर्ग सात या दस सालों के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन का नामोनिशान तक मिटा देने की डींगें मार रहे हैं।

आपरेशन ग्रीनहंट के अंतर्गत जनता पर युद्ध और ज्यादा तीव्र हो गया। अब तक दण्डकारण्य में करीब 400 जनता और क्रांतिकारी कार्यकर्ता इस हमले में मारे जा चुके हैं। दक्षिण बस्तर के सिंगारम में 17 आदिवासियों के खून की होली के साथ भाजपा ने अपने शासन की दूसरी पारी का 'शुभारंभ' किया। उसके बाद 2009 से सामूहिक हत्याकाण्डों का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। वेच्चापाड़–एटेपाड़, गोम्पाड़, सिंगनमडुगू–गच्चनपल्ली–गट्टापाड़, टेट्टेमडुगू–पालोड़–डोकुपाड़, जेगरगोण्डा, गोल्लागूडेम, पूजारी कांकेर, गोण्डमेट्टा, कोकावाड़ा, गुमियापाल, ताकिलोड़, ओंगनार, सारकिनगुड़ा, एड्समेट्टा आदि दर्जनों नरसंहारों को रमन सरकार ने अंजाम दिया। मार्च 2011 में चिंतलनार इलाके के मोरपल्ली, पुलानपल्ली, तिम्मापुर और ताड़िमेट्ला गांवों में भारी तबाही और हत्याकाण्ड मचाया गया। कार्पेट सेक्यूरिटी के तहत हर 3–5 किलोमीटर के दायरे में एक अर्द्धसैनिक/पुलिस कैम्प खोलकर समूचे दण्डकारण्य क्षेत्र को सैन्य छावनी में

तब्दील किया गया। दसियों हजार की संख्या में अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस व कमाण्डो बलों को तैनात कर उसकी संख्या को रोज–रोज बढ़ाते जा रही है।

सरकार अपनी प्रतिक्रांतिकारी एलआईसी रणनीति के तहत एक ओर भारी दमनचक्र चलाते हुए ही दूसरी ओर सुधारों को भी एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसी को 'दोहरी रणनीति' बताया जा रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम से कपड़े, साइकल, बर्तन, टीवी, खेलकूद की सामग्री आदि बांटते हुए 'जनता का दिलोदिमाग जीतने' की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर पक्की सड़कें, पुल आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कई किस्म की छलकपटपूर्ण चालें चल रहे हैं ताकि जनता में फूट डाली जा सके। आत्मसमर्पण योजना, क्रांतिकारियों के परिवार वालों से परामर्श, मुखबिर नेटवर्क, दुष्प्रचार आदि को बढ़ा दिया है। और भी कई अन्य नए–नए रूपों में सरकारी हमला चल रहा है।

गांवों में हमलों के दौरान जनता को बुरी यातनाएं देना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, पकड़े गए लोगों को बुरी यातनाएं देकर फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेजना आदि बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जेलों के अंदर तीन हजार से ज्यादा आदिवासी कैद हैं। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों और दमन का खण्डन करने के 'जुर्म' पर डाक्टर बिनायक सेन को, क्रांतिकारी साहित्य रखने के आरोप में पत्रिका सम्पादक असित सेनगुप्ता को, स्वतंत्र पत्रकार प्रफुल्ल झा, लिंगाराम कोड़ोपी आदि जनवादियों को भी जेल में डालकर, राजद्रोह के तहत केस लगाकर, कड़ी सजाएं देने का 'श्रेय' भी छत्तीसगढ़ सरकार को ही जाता है। जेलों के अंदर हालात बेहद अमानवीय हैं। जमानत पर रिहा होने के अधिकार का पूरी तरह हनन हो गया। जेलों में सही खाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। खासकर महिलाएं कई समस्याएं झेल रही हैं। इसके अलावा कड़ी सजाएं और आजीवन कारावास की सजाएं सुनाना भी छत्तीसगढ़ सरकार की सुनियोजित रणनीति है।

नक्सलवादियों को 'विकास विरोधी' बताकर दुष्प्रचार करने वाली भाजपा सरकार जनता की पहलकदमी से निर्मित हो रही नई अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए क्रूर दमनचक्र चला रही है। सलवा जुडूम के दिनों में गांवों में हमलों के दौरान फसलों, जनता की सम्पत्तियों, घरों, धान की चक्कियों, फलदार पेड़–पौधों को अंधाधुंध तबाह करने की अनगिनत घटनाएं हुई थीं। ग्रीनहंट के तहत जारी मौजूदा चरण में गांवों में जनता द्वारा संचालित आश्रम शालाओं और कृषि क्षेत्रों को खासतौर पर निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। नारायणपुर

जिले के कुमुड़गुण्डा (उत्तर बस्तर), तिरका (पूर्व बस्तर), गट्टाकल (माड़); बीजापुर जिले के तुमनार और जप्पूर (पश्चिम बस्तर); सुकमा जिले के पुव्वर्ति (दक्षिण बस्तर) आदि गांवों में जनता द्वारा क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में चलाई जा रही आश्रम शालाओं को सरकारी सशस्त्र बलों ने जलाकर राख कर दिया। छात्रों के कपड़ों, किताबों और अन्य सामग्री को आग के हवाले कर दिया। इस तरह जनता और छात्रों में दहशत का वातावरण निर्मित किया गया।

विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रति हमारा रुख

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने पिछले दस सालों से जन विरोधी, दमनकारी, देशद्रोहपूर्ण और फासीवादी शासन चलाया। और दस सालों से केन्द्र में सत्ता पर काबिज रहते हुए प्रदेश में मुख्य विपक्ष के तौर पर रही कांग्रेस अब गुटबाजी में बुरी तरह डूबी हुई है। जन विरोधी एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण) की नीतियों पर अमल और जन आंदोलनों के दमन की नीतियों के मामले में इन दोनों पार्टियों के बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है। राज्य में मौजूद प्राकृतिक सम्पदाओं को बड़े पूंजीपतियों और विदेशी कम्पनियों के हाथों लुटाने वाली देशद्रोहपूर्ण नीतियों में दोनों का रुख एक जैसा ही है। इसलिए ये दोनों पार्टियां जन हित और जन कल्याण की राह में बहुत बड़े रोड़े बनी हुई हैं। सिर्फ अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के लिए या जनता के दबाव से मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी और व्यक्तिगत तौर पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कुछ मौकों पर आदिवासियों के नरसंहारों का खण्डन किया। हालांकि यह गौरतलब है कि फिलहाल प्रदेश में तमाम दमनकारी नीतियां केन्द्र सरकार की शह पर और उसके पूरे सहयोग से लागू हो रही हैं। इसलिए दोनों कांग्रेस और भाजपा को गांवों में घुसने ही नहीं देना चाहिए, अगर आते हैं तो मार भगा देना चाहिए।

बस्तर और कुछ अन्य इलाकों में कुछ सीटों पर लड़ने वाली संशोधनवादी सीपीआई सतही तौर पर ही सरकारी नीतियों की आलोचना करती है और उन पर जन आंदोलन चलाने व जन हितों की रक्षा करने में उसमें ईमानदारी का अभाव है। विस्थापन के मुद्दे पर वह कार्पोरेट लूटखसोट की नीतियों का विरोध न करते हुए, उसके खिलाफ दृढ़ता से न लड़ते हुए 'विस्थापन से पहले व्यवस्थापन' की दिवालिया नीति अपना रखी है। यानी पहले पर्याप्त मुआवजा देकर जमीनें छीनी जा सकती हैं। एक ओर सीपीआई सलवा जुडूम और आपरेशन ग्रीनहंट का विरोध कर रही है लेकिन वहीं दूसरी ओर वह यह कहते हुए कि आदिवासी दो पाटों के बीच पिस रहे हैं और माओवादी हिंसा कर रहे

हैं, जन प्रतिरोध पर के औचित्य पर सवालिया निशान लगाते हुए दिवालिया बयान दे रही है। वहीं सीपीएम के नेतृत्व वाले 'वाम' मोर्चे द्वारा पश्चिम बंगाल में दशकों तक चलाया गया सामाजिक फासीवादी शासन और उसके द्वारा अमल कार्पोरेट–परस्त तथा जन विरोधी नीतियों का अनुभव सामने है। खासकर 25 मई की कार्रवाई में जब सलवा जुडूम का सूत्रधार, हत्यारा और बस्तरिया जनता का दुश्मन महेन्द्र कर्मा समेत कुछ अन्य कांग्रेसी नेता मारे गए थे, सीपीएम और सीपीआई ने उसका खण्डन कर अपने जन विरोधी चरित्र को उजागर किया। इस तरह उन्होंने यह साबित किया कि वे अपनी आत्मरक्षा और अस्तित्व के लिए संघर्षरत जनता के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि शोषक शासक वर्गों की तरफ ही उनका झुकाव है। क्रांतिकारी लाइन से कब का नाता तोड़ चुकी और मार्क्सवाद की रट मात्र ही लगाने वाली संशोधनवादी सीपीआई और सीपीएम इन चुनावों में जैसे–तैसे कुछ सीटें हासिल कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इन पार्टियों को जनता में कोई उल्लेखनीय आधार नहीं है फिर भी कुछ समस्याओं को लेकर, खासकर सीपीआई द्वारा सरकारी दमन के खिलाफ कुछ मौकों पर अपनाए गए कार्यक्रमों में जनता भाग ले रही है। इस जन गोलबंदी का चुनावी फायदा उठाने के लिए संशोधनवादी पार्टियां कई तिकड़म करती हैं। इसलिए इनके चरित्र के बारे में हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।

खुद को दलितों और उत्पीड़ित तबकों का प्रतिनिधि बताने वाली बीएसपी वास्तव में सामंती और दलाल बुर्जुआ वर्गों का प्रतिनिधि है, यह बात काफी पहले ही साफ हो चुकी है। उत्तरप्रदेश में उस पार्टी की नेता मायावती के शासनकाल में बेरोकटोक लागू जन विरोधी, फासीवादी–दमनकारी और नव उदार नीतियां इस बात का साफ सबूत है। छत्तीसगढ़ में इस पार्टी की कोई खास ताकत नहीं होने के बावजूद कुछ सीटों पर वह लड़ रही है। सदियों से दमन, उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार रहे दलितों और अन्य शोषित तबकों के बहुत कम लोगों के अंदर ही सही बीएसपी पर अभी भी कुछ भ्रम मौजूद हैं।

पी.ए. संगमा के नेतृत्व में गठित नेशनल पीपुल्स पार्टी में बस्तर के आदिवासी नेता और पूर्व सांसद अरविंद नेताम आदि के शामिल हो जाने और उसके आदिवासी रंग होने से यह उम्मीद की जा रही है कि उसे कुछ सीटें मिल जाएं। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वालों में अरविंद नेताम प्रमुख हैं। साथ ही, यह पार्टी छठवीं अनुसूची लागू करने की मांग भी कर रही है। ये लोग वोटों और सीटों के लिए ही आदिवासी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि आदिवासियों के असली मुद्दों पर, जल–जंगल–जमीन पर अधिकार के मुद्दे पर इनका कोई स्पष्ट राय नहीं है। गोण्डवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ नाम के वास्ते ही आदिवासियों

की पार्टी है लेकिन उसने आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों पर स्पष्ट रुख के साथ आंदोलन कम ही चलाए। मुख्य रूप से आदिवासियों पर जारी फासीवादी सरकारी दमन के खिलाफ उसने कभी दृढ़तापूर्ण रुख नहीं अपनाया। आदिवासियों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बने विस्थापन के मुद्दे पर इसने जनता को गोलबंद करने और आंदोलन खड़ा करने की कहीं कोशिश की हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जैसे–तैसे कुछ सीटें हासिल कर किसी न किसी पार्टी का पिछलग्गू बन जाना ही इसका लक्ष्य दिखाई पड़ता है। हालांकि अस्मिता के मुद्दे पर इस पार्टी ने कुछेक बार आदिवासियों को गोलबंद किया।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच आदि छोटी–मोटी पार्टियां भी चुनावी दंगल में हैं। इनमें से पहले सात पार्टियों ने मिलकर तीसरे मार्चे के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन बाद में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने खुद को इस मोर्चे से अलग करने की घोषणा की। ज्यों–ज्यों नामांकन की तारीख नजदीक आएगी, तीसरा मोर्चा कितने टुकड़ों में बंट जाएगा कहना मुश्किल है। कांग्रेस और भाजपा में किसी को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में 'किंगमेकर' की भूमिका निभाने के लिए ही तीसरा मोर्चा काम आ सकता है। इन लोगों को कांग्रेस और भाजपा से अलग न कोई स्वतंत्र कार्यक्रम है न ही कोई अलग एजेण्डा है। जन समस्याओं के हल के लिए इन लोगों के पास कोई नया समाधान भी नहीं है।

क्रांतिकारी जनताना सरकार ही सही विकल्प है!

हमारी पार्टी शुरू से ही क्रांतिकारी संघर्ष के तमाम इलाकों में चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम लागू करते आ रही है। इस शोषणकारी व्यवस्था को सशस्त्र संघर्ष के जरिए ही, दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते से ही बदला जा सकता है, जनता को यह समझाते हुए चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते आ रही है। 'इलाकावार राजसत्ता पर दखल' के लिए जनयुद्ध का संचालन करते हुए हम आज आधार इलाके के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले तीस सालों से जारी वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप कई गांवों में शोषक वर्गों और प्रतिक्रियावादी सामंती ताकतों की सत्ता को खत्म कर जनता द्वारा स्थापित 'क्रांतिकारी जनताना सरकार' आज एरिया और डिवीजन स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ रही है। वह जनता के सच्चे विकास को केन्द्र बिंदु बनाकर क्रांतिकारी सुधारों को प्राथमिक स्तर पर ही सही लागू कर रही है। ये क्रांतिकारी सुधार शोषक सरकारों द्वारा लागू झूठे सुधारों से पूरी तरह भिन्न हैं। ये जनता को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले हैं। उत्पादन में उसकी भागीदारी को बढ़ाने वाले हैं।

इन क्रांतिकारी सुधारों के तहत मुख्य रूप से उत्पादन के तरीके में बदलाव लाने, पैदावार बढ़ाने, उससे जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अंतर्गत क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में पिछले तीन सालों में लिए गए अभियानों में लाखों जनता ने भिड़कर हजारों एकड़ जमीन का समतलीकरण कर लिया। कई नए तालाबों, डबरियों और कुओं को खोद लिया। पुराने तालाबों और डबरियों का गहरीकरण और मरम्मत के कार्य किए।

भूमिहीनों के लिए क्रांतिकारी जनताना सरकार वन भूमि पर कब्जा कर और प्रतिक्रियावादी भूस्वामियों से छीनी हुई जमीनें बांटकर क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू कर रही है।

क्रांतिकारी जनताना सरकार के प्रयासों के चलते पिछले कुछ समय से कुछ जगहों पर जनता में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ा है जिससे पैदावार भी बढ़ी है। इसका प्रचलन पहले उतना ज्यादा नहीं था। साथ ही, तालाबों से नहरों के जरिए पानी बहाकर खेतों को सिंचित करने का क्रम भी यहां पर शुरू हुआ है। कई नई साग–सब्जियां उगाई जा रही हैं जो पहले प्रचलन में नहीं थीं। फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। कई तालाबों में मछली पालन कर जनता अपने लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर ले रही है।

दुश्मन के हमलों के चलते जोताई आदि काम अस्थाई तौर पर रुक जाने पर भी हमलों के बीच ही जनता उन्हें फिर से जारी रख रही है। युद्ध के बीच ही उत्पादन के कामों को जारी रखते हुए पैदावार को बढ़ाकर अपने जीवन स्तर को सुधार लेने की चेतना जनता के अंदर बढ़ रही है। यह उसी का नतीजा है।

आपसी श्रम सहकारिता से लोग घर बना ले रहे हैं। पीने के पानी की सुविधाएं बेहतर बना रहे हैं।

शोषक सरकारों ने जो कभी नहीं किया, वह काम क्रांतिकारी जनताना सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रही है। गांव–गांव में लोगों को उपलब्ध हो रही इन सुविधाओं में पिछले पांच सालों में कुछ हद तक विकास देखा गया है। सलवा जुडूम के दौरान यहां पर नाम के वास्ते ही रही स्कूलों को भी सरकार ने जब पुलिसिया अड्डों में तब्दील किया तो क्रांतिकारी जनताना सरकार ने उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश की। फिलहाल दण्डकारण्य भर में कई आश्रम शालाएं संचालित हो रही हैं। जन वैद्य हर साल आने वाली मौसमी बीमारियों से जनता को बचाते हुए असमय मौतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

महिलाओं के जीवन से जुड़े कई बदलाव क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में संभव हो पाए हैं। जबरिया विवाह, बहुपत्नीत्व आदि रिवाज काफी हद तक कम हो चुके हैं। जन सरकार द्वारा वितरित जमीनों पर परिवार के पुरुष मुखिया के साथ–साथ महिला को भी बराबर का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं पर विभिन्न रूपों में जारी भेदभाव और अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष और शिक्षा का सिलसिला जारी है। इसके फलस्वरूप महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बाहरी समाज में जहां आज महिलाओं को सुरक्षा का घोर अभाव है वहीं यह बात गर्व से कही जा सकती है कि जहां क्रांतिकारी जनताना सरकार संचालित है वहां पर महिलाओं को काफी हद तक सुरक्षा प्राप्त है। साथ ही, संस्कृति के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी जनताना सरकार ने कई बदलाव लाए हैं। समाज में सदियों से जारी अंधविश्वासों, सड़ी–गली सामंती संस्कृति और जहरीली साम्राज्यवादी संस्कृति के खिलाफ जनता को निरंतर चेतनाबद्ध किया जा रहा है।

क्रांतिकारी जनताना सरकार के नेतृत्व में, विभिन्न संगठनों के प्रत्यक्ष नेतृत्व में जनता हर साल लड़कर तेंदुपत्ता की मजदूरी दरों को सरकार द्वारा घोषित नाम मात्र की दरों से कहीं ज्यादा बढ़ा ले रही है। साथ ही, विभिन्न वनोपजों और फसलों को सही दाम की मांग करते हुए संघर्ष कर रही है। इसमें जनता को उल्लेखनीय उपलब्धियां मिली हैं। मजदूरी के कामों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी का भुगतान हो रहा है।

क्रांतिकारी जनताना सरकार हजारों जनता को मिलिशिया के रूप में संगठित कर रही है। जन मिलिशिया अपने गांवों और अपनी जनता को दुश्मन के हमलों से बचा रही है। खासकर खेतों की जोताई और फसल कटाई के समय दुश्मन के हमलों का मुकाबला करते हुए जन जीवन की रक्षा कर रही है।

यहां पर साम्राज्यवादियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित कई परियोजनाओं, भारी उद्योगों और खदानों को क्रांतिकारी जनताना सरकार रोक रही है और इस तरह जनता को विस्थापन की समस्या से बचा रही है।

इन प्रयासों के फलस्वरूप मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था के असली विकल्प के रूप में 'क्रांतिकारी जनताना सरकार' पर शोषित जनता का विश्वास बढ़ रहा है। इस तरह दिनोंदिन संगठित हो रही जनता की नई सत्ता देश भर में जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए उसके लिए आशा की किरण बनी हुई है।

प्यारे लोगो,

छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार करने के आह्वान के साथ हमारी पार्टी एक व्यापक राजनीतिक अभियान शुरू कर रही है। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जनता को सच्चे लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का कार्यक्रम किसी भी शोषक पार्टी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारी जनताना सरकार के पास ही है। हमें यह नारा बुलंद करना चाहिए कि इस शोषणमूलक व्यवस्था का असली विकल्प 'क्रांतिकारी जन कमेटियां' ही है। जिस प्रकार वोट डालना एक जनवादी अधिकार है, वोट नहीं डालना और चुनावों का बहिष्कार करना भी जनता का जायज और जनवादी अधिकार है। इस लुटेरी व्यवस्था पर और चुनाव प्रणाली पर, जो उसका हिस्सा है, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सर्वोच्च अदालत को भी यह फैसला देना पड़ा कि मतदाताओं को अगर कोई भी उम्मीदवार पसंद न आए तो 'इनमें से कोई नहीं' का विकल्प भी होना चाहिए। दूसरी ओर आपराधिक चरित्र वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले फैसले को भी उलटने को लेकर सत्ता के गलियारों में खूब खींचतान मची हुई है। यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि चुनाव लड़ने वालों में अत्यधिक लोग आपराधिक प्रवृत्ति वाले ही होते हैं चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों न हो। यह करोड़पतियों और अरबपतियों का चुनाव है जिसमें मामूली इन्सानों का घुसना तक मना है। 'जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का' कहकर लोकतंत्र की जो परिभाषा दी जाती है वह कोरी बकवास है। संसद, विधानसभाओं में बैठे हुए लोगों को देखकर भी यह साफ समझा जा सकता है कि यह लोकतंत्र अत्यंत धनाढ्यों के हाथ का खिलौना है।

खास तौर पर चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम को विफल करने के इरादे से, यानी जनता से वोट न डालने के जनवादी अधिकार को छीनने के लिए शोषक शासक वर्गों ने व्यापक दमन अभियान छेड़ रखे है। इसका मुकाबला करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर जन प्रतिरोध खड़ा करना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के मजदूरों, किसानों, छात्र–बुद्धिजीवियों, लेखक–कवियों, पत्रकारों–मीडियाकर्मियों, शिक्षकों–अध्यापकों – तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वे शोषक–लुटेरों के इन ढोंगी चुनावों का बहिष्कार करें और दण्डकारण्य समेत देश के विभिन्न इलाकों में आकार ले रही जनता की जनवादी हुकूमत, यानी क्रांतिकारी जनताना सरकार का स्वागत करें और उसके समर्थन में उठ खड़े हों।

25 सितम्बर 2013

★ संसद-विधानसभा सुअरबाड़ा है! बलवाई-गुण्डों का अखाड़ा है!
★ जनता की मुक्ति जनयुद्ध से ही संभव है, फर्जी चुनावों से नहीं!
★ संसदीय चुनावों से नहीं, संघर्ष से ही बदलेगी व्यवस्था!
★ जनयुद्ध को तेज कर आपरेशन ग्रीनहंट को हरा दो!
★ जल-जंगल-जमीन पर अधिकार जनता का हो!
★ क्रांतिकारी जनताना सरकार को मजबूत करो! फैला दो!
★ विकास के नाम पर सेज, माइनिंग, बड़ी परियोजनाओं और अभयारण्यों के नाम से जनता को उजाड़ने की नीतियों का विरोध करो!
★ सिंगारम से लेकर एड़समेट्टा तक हुए तमाम नरसंहारों व फर्जी मुठभेड़ों के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कोया कमाण्डो/एसपीओं को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दो!
★ जेलों में बंद तमाम राजनीतिक बंदियों और निर्दोष आदिवासियों को बिना शर्त रिहा करो!
★ मंहगाई, विस्थापन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अकाल के खिलाफ जोरदार जन आंदोलनों का निर्माण करो!
★ मजदूर-कर्मचारियों की छंटनी, वेतन कटौती, तालाबंदी, ठेकेदारी प्रथा और मशीनीकरण का विरोध करो!
★ महिलाओं पर हो रहे तमाम अत्याचारों - बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, टोनही हत्या, घरेलू हिंसा, भेदभाव, पितृसत्तात्मक दमन के खिलाफ व्यापक संघर्ष करो!
★ उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष करो!
★ सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद, साम्राज्यवाद को दफना दो!
★ दुनिया का एक नम्बर दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!
★ नई जनवादी क्रांति जिन्दाबाद!

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ...

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भाकपा (माओवादी)